

आजाद सिपाही



मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिद्धकोफेड के निदेशक पर्सद की बैठक हुई

छूटे हुए किसानों को लैम्पस-पैक्स से निबंधन करारें: हेमंत सोरेन

किसानों को वैकल्पिक कृषि और वन उद्योग के लिए प्रशिक्षण दें
आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्धो-कांठू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (सिद्धकोफेड) के निदेशक पर्सद की तृतीय बैठक मंगलवार को हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सिद्धकोफेड गठन हुआ है। इसका उद्देश्य विभिन्न वनोपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करना है। ऐसे में इस सहकारी संघ की जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे इससे

जुड़ कर उत्पादों का लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैम्पस और पैक्स से आज भी किसानों की एक बड़ी संख्या निबंधित नहीं है। ऐसे में छूटे हुए सभी किसानों को जोड़ने की पहल करें। लैम्पस-पैक्स भवनों की मरम्मत के साथ उसके उचित रखरखाव और बेहतर प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था हो।

उत्पादों का वैल्यू एडिशन के साथ जियो टैगिंग हो: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लाह, इमली, कोदो, कुटकी, सरगुजा, चिरौंजी, आंवला, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसे कई वनोपज हैं, जिसकी उपयोगिता और बाजार में काफी ज्यादा मांग है। इसके उत्पादकों को इसका उचित फायदा नहीं मिल रहा है। झारखंड के इन विशेष उत्पादों का वैल्यू एडिशन के साथ जियो टैगिंग करने की दिशा में कदम



उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठावें

हेमंत सोरेन ने कहा कि वनोपज एवं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने चाहिए। किसानों को जोड़ें और प्रशिक्षण दें। लाह तथा रेशम-तसर की खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में पहल करें।

उठावें, ताकि इन वनोपजों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ किसानों को पूरा फायदा मिल सके। वैकल्पिक कृषि के लिए किसानों को प्रशिक्षित करें: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस तरह मौसम में उतार चढ़ाव के कारण परंपरागत कृषि काफी

केंद्र पता को भी संघ के दायरे में लाने की संभावनाएं तलाशें

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि केंद्र पता वनोपज को भी सिद्धो-कांठू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के दायरे में लाने की संभावनाएं तलाशें। इससे केंद्र पता के उत्पादन से जुड़े श्रमिकों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि फुदी स्थित नवनिर्मित सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाये। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय सहकारी संघ अथवा राष्ट्रीय प्रशिक्षण सहकारी परिषद् से एमओयू कर वहां प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज करवाया जाये। ताकि राज्य के नवयुवकों का रिस्कल डेलवपमेंट हो और रोजगार मिल सके।

प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसानों को वैकल्पिक कृषि के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कृषक पाठशाला में किसानों को वैकल्पिक खेती का प्रशिक्षण दें।

मधु संग्रहकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये: बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि मधु संग्रहकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये। उनका समूह बना कर सिद्धकोफेड से जोड़ा जाये। उनके

मुख्यमंत्री मंडियां सम्मान योजना

हेमंत ने उपायुक्तों के साथ की बैठक

रांची (आजाद सिपाही)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मंडियां सम्मान योजना को लेकर जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने योजना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसमें आ रही तकनीकी समस्याओं से अवगत हुए। इस बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हेमंत ने अधिकारियों को तत्काल समस्या का निदान करने का आदेश दिया। बैठक में विभाग के वरीय अधिकारियों के अलावा जिला उपायुक्तों, सीएससी के वरीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे।

आजीवन सजा काट रहे 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति

रांची (आजाद सिपाही)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्सद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन 67 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर पुनः विचार किया गया, जिन्हें पिछली दो बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोवेंशन पदाधिकारी के मंतव्य पर अनुरोधों के साथ विचार विचार-विमर्श के उपरान्त 30 कैदियों को रिहा किये जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

विदेश मंत्री ने संसद में बांग्लादेश के हालात की दी जानकारी हिंदुओं पर हो रहे हमले: जयशंकर

- सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की
- राष्ट्रपति ने बांग्लादेश में संसद भंग किया
- पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी रिहा



आजाद सिपाही संवाददाता

नयी दिल्ली। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव देंगे। दूसरी तरफ, भारत सरकार ने मंगलवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना सदमे में हैं। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वह भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। उधर, विदेश मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यह चिंता की बात है। हालात पर भारत की नजर है।

दरअसल, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दो महीने से

व्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है: राहुल

नयी दिल्ली (आजाद सिपाही)। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूद हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? इस पर सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमैट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें

जारी प्रदर्शन में सोमवार को जम कर हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ढाका से अमरतला के रास्ते भारत पहुंची

बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर: जयशंकर

नयी दिल्ली (आजाद सिपाही)। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सरकार ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों को हालात के बारे में बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर नजर रख रहा है। अपने राजनयिक मिशनों के जरिए हम वहां के भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। पड़ोसी देश में इस जटिल और अभी भी लगातार अस्थिर बने हुए हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने को लेकर भी सरकार का रुख भी साफ किया। जयशंकर ने बताया कि अनुमान है कि पड़ोसी देश में 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। हालांकि, ज्यादातर छात्र जुलाई के महीने में ही भारत लौट आये।

थीं। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनसे करीब एक घंटे बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं।

बरही में पवनपुत्रा स्टील प्लांट में ब्लास्ट, एक मौत

बरही (आजाद सिपाही)। बरही में रियाज की जमीन में संचालित पवन पुत्रा नामक फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गयी, जबकि करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गये। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कंपनी में एक शिफ्ट में 14 मजदूर काम करते थे। इस हादसे में सभी मजदूर फंस गये। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

हाइकोर्ट ने कहा: ऐसे सफेदपोश राष्ट्र के विकास में हैं बाधक सुमित गुप्ता को नहीं मिली बेल

781 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781.39 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी

खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है। लेकिन आरोपी सुमित गुप्ता जैसे व्यक्ति जो सफेदपोश अपराधी हैं, वे फर्जी कागज और फर्म बना कर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी

करके और व्यक्तिगत लाभ गिद्ध दृष्टि रख कर सार्वजनिक धन की हानि करके राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है। समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए।

झारखंड आंदोलनकारियों के दिन बहुरेंगे

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आंदोलनकारियों को सूची तैयार
दुमका में 79, रांची 304, जामताड़ा में 301 नये आंदोलनकारी

अजय शर्मा

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड अलग राज्य के निर्माण के दौरान हुए आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के दिन बहुरेंगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आंदोलनकारियों को चिह्नित करने वाले आयोग ने इसकी सूची तैयार कर ली है। जल्द ही इस फाइल पर सीएम की सहमति हो जायेगी। आंदोलनकारियों के अधिकांश मामले राज्य सरकार पहले ही वापस ले चुकी है। कई के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए जामुमो



कितनी मिलेगी पेंशन

छह माह से अधिक जेल में रहनेवाले आंदोलनकारियों को 7 हजार रुपये नगद प्रतिमाह। छह माह से कम और तीन माह से ज्यादा जेल में बंद आंदोलनकारियों या उनके परिजन को प्रतिमाह 5 हजार रुपये मिलेंगे। तीन माह से कम जेल में बंद रहनेवाले आंदोलनकारियों या उनके परिजनों को तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।

के सुप्रीमो शिवू सोरेन की अगुवाई में भी करीब दो दशक तक आंदोलन किया गया। इस दौरान करीब 10 हजार लोग जेल गये थे। कई बहनों का भाई और कई महिलाओं का पति छिन गया था। वैसे परिवारों की

सूची अलग से तैयार की जा रही है। आंदोलनकारियों को मिलनेवाले लाभ में मुख्य रूप से पेंशन है। अभी जो सूची तैयार की गयी है, उसमें राज्य भर के 2997 आंदोलनकारी चिह्नित किये गये हैं।

नये आंदोलनकारियों की संख्या

बोकारो 57, चतरा 89, देवघर 145, पश्चिम सिंहभूम 74, सरायकेला खरसावां 111, साहिबगंज 3, रांची 304, रामगढ़ 177, पलामू 47, लोहरदगा 65, लातेहार 5, खूंटी 18, जामताड़ा 301, हजारीबाग 256, गुमला 08, गोड्डा 277, गिरिडीह 431, गढ़वा 27, पूर्वी सिंहभूम 489, दुमका 79 और धनबाद में 34 आंदोलनकारी नये चिह्नित किये गये हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।

ऐसे तैयार की गयी है सूची : आंदोलनकारियों की सूची आंदोलन के दौरान दर्ज एकआइआर और जेल के रिकार्ड से तैयार की गयी है। इसके लिए आंदोलनकारी चिह्नितकरण आयोग का गठन किया गया है।

#RememberingBauji

A tribute to the son of soil
on his 94th birth anniversary

We commemorate the visionary spirit of Shri O.P. Jindal, whose bold dreams transformed industries and empowered communities. His indomitable legacy lives on in the heart of every endeavour at Jindal Group.

Shri O. P. Jindal
7th August 1930 - 31st March 2005
Founder and Visionary, O. P. Jindal Group

Remembering Bauji Today... and Every Day...



बांग्लादेश में हिंसा, बदलाव की मांग या साजिश!

- चुन-चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी
- भारत को अलर्ट रहने की जरूरत, घुसपैठिये एक्टिव
- बांग्लादेशी सीमा पर हरकत, सीमावर्ती राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने का सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा को लेकर जतायी जा रही है। इस हिंसा का कारण केवल बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति ही नहीं है। इसके पीछे भारत विरोधी देशों का भी हाथ माना जा रहा है। कुछ का तो यहां तक दावा है कि बांग्लादेश की इस स्थिति के पीछे अमेरिका का हाथ है, वहीं कुछ आइएसआइ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि अमेरिका इन इलाकों में अपना दखल मजबूत करना चाहता है। समझा जा सकता है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। जो भी हो, भारत को अब सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाइ अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश

से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी सतर्कता से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने अपनी निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। किसी तरह की घुसपैठ न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा बल को पूरी तरह से नजर बनाये रखने को कहा गया है। सभी संवेदनशील एंटी प्वाइंट को चिह्नित कर वहां खास चौकसी रखने का निर्देश दिया गया है। खुफिया जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में जारी अशांति के दौरान कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गये हैं। इनके भारत में प्रवेश करने की आशंका से

आजाद सिपाही विशेष

बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। उस वक्त हसीना ने प्रणय को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया था कि विरोधी ताकतें उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। आंदोलनकारियों के जुलूस के पीएम हाउस की ओर निकलने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। वे सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली आयीं। आजादी के बाद बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ

एजेंसियां चौकन्ना हैं। ये आतंकी संगठन भारत-बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। सूत्रों की मानें, तो 31 जुलाई को

रहा है। तख्तापलट के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मंदिर, गुरुद्वारे, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कट्टरपंथी लगातार इन्हें निशाना बना रहे हैं। हिंसा और आगजनी के बीच अब उपवृत्ति चुन-चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। घरों में आग लगायी जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा है, जहां सांप्रदायिक हमले न हुए हों। कैसे बांग्लादेश हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, कैसे वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है और कैसे अब बांग्लादेशी घुसपैठिये एक्टिव हो सकते हैं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।



राकेश सिंह

आरक्षण की आड़ में राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय साजिश

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने का सीधा असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की कई व्यापारिक परियोजनाएं बांग्लादेश के साथ क्रियान्वयन के स्तर पर हैं। अब इसका सीधा असर देश की कई कंपनियों पर भी पड़ेगा। उपद्रव के बाद वहां से पलायन होता है, तो इसका सीधा दबाव भारत पर पड़ना तय है। पड़ोसी देश में अस्थिरता और अराजकता का असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। जानकारों की मानें, तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय साजिशों से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आरक्षण के जिन से निपटने में शेख हसीना सरकार फेल हो गयी। बांग्लादेश के आजाद होने के बाद वहां की सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। इसके बाद उनकी संतानों और अब चौथी पीढ़ी को आरक्षण दिया जा रहा है। इसका विरोध वहां के लोग ही कर रहे हैं। हाइकोर्ट के फैसले के बाद शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी को इंजाम करने को कहा, लेकिन इससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उपद्रव शुरू कर दिया। जानकारों की मानें, तो बांग्लादेश की सेना भी इस आंदोलन को हवा दे रही है। सेना ने ही तख्ता पलट कराया है और अब वही शासन की बागडोर संभालने को तैयार है। सेना के

प्रमुख शेख हसीना के रिश्तेदार ही हैं। एशियाई देशों में देखा गया है कि सैन्य शक्तियों ने लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभायी है। भारत इसका अपवाद है, क्योंकि भारत में सैन्य शक्तियों का प्रमुख भी राष्ट्रपति को बनाया गया है। बांग्लादेश के मौजूदा अराजक माहौल की वजह से बड़ी तादाद में शरणार्थियों के भारत आने का खतरा बढ़ रहा है। भारत सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। राज्य सरकारों की मदद से शुरुआती स्तर पर ही समस्या को नियंत्रित करना होगा, जिससे बांग्लादेशी शरणार्थी भारत की आबादी के लिए खतरा न बनें। भारत के आसपास के देशों में सत्ता का संघर्ष कई सालों से निरंतर चल रहा है। पूरब-पश्चिम और दक्षिण तीनों ही दिशा में अस्थिरता बढ़ रही है। इससे हिंद महासागर में चीन के दखल की आशंका भी बढ़ रही है। इस अस्थिरता के लिए चीन की साम्राज्यवादी सोच को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत सरकार के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में जिसके भी हाथ में सत्ता की बागडोर आये, उसके साथ समन्वयवादी तरीका अपना कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे।

घुसपैठिये एक्टिव

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाइ अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी सतर्कता से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने अपनह निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। किसी तरह की घुसपैठ न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से नजर बनाये रखने को कहा गया है। बीएसएफ ने 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर एहतियात बरतने के निर्देश दिये हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। डीजी ने उत्तर 24 परगना जिले की सीमा का दौरा भी किया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से लगती भारत-बांग्लादेश सीमा पर



अमुदिया सीमा चौकी के पास 10-15 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। ऐसे सभी संवेदनशील एंटी प्वाइंट को चिह्नित कर वहां खास चौकसी रखने को कहा गया है। बांग्लादेश की तरफ से नदिया जिले के मनुआपाड़ा, हलदरपाड़ा, बानपुर और मैटियारी में घुसपैठ की कोशिश की आशंका को देखते हुए खास निगरानी की जा रही है। मुर्शिदाबाद जिले के चरमराशी और मालदा जिले में सासनी सीमा चौकी के इलाके भी संवेदनशील बताये जा रहे हैं। बीएसएफ ने बॉर्डर गाइड्स बांग्लादेश के साथ भी संपर्क कायम किया है।

आतंकीयों से खतरा

खुफिया जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में जारी अशांति के दौरान कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गये हैं। इनके भारत में प्रवेश करने की

आशंका से एजेंसियां चौकन्ना हैं। ये आतंकी संगठन भारत बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। कई मौकों पर भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल और असम से इन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संदेह है कि मौजूदा उथल-पुथल का फायदा उठा कर इन आतंकवादी संगठनों के सदस्य भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें असम में 262, त्रिपुरा में 856, मिजोरम में 318, मेघालय में 443 और पश्चिम बंगाल में 2,217 किलोमीटर की सीमा शामिल है। इन सभी स्थानों पर राज्य सरकारों को भी अलर्ट भेजा गया है।

आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना

बांग्लादेश में हालात इतने बदतर हो गये हैं कि हिंदुओं के घरों और

निशाना बनाया गया, क्योंकि कई पाकिस्तानी उन्हें अलगाव के लिए दोषी मानते थे। इससे हिंदू आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई। 1951 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) की कुल आबादी में हिंदू 22 प्रतिशत थे। यह संख्या 1991 तक घट कर 15 प्रतिशत रह गयी। 2011 की जनगणना में यह संख्या केवल 8.5 प्रतिशत रह गयी। 2022 में यह आठ प्रतिशत से भी कम हो गयी है। वहीं मुसलमानों की आबादी 1951 में 76 प्रतिशत से 2022 में 91 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1.1 करोड़ से अधिक हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भाग गये। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़ कर चले जाते हैं। 2011 की जनगणना से पता चला कि 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से दस लाख हिंदू गायब हो गये।

कैसे हसीना आयी भारत

31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक, उस वक्त हसीना ने प्रणय वर्मा को अपनी जान के खतरे से अवगत कराया था। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। इसके बाद प्रणय वर्मा ने यह जानकारी नयी दिल्ली के साथ साझा की। बांग्लादेश में हुई इस उठापटक से पहले ही तीन दिनों की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गयी। सेना को स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। आर्मी चीफ वकार-उज-जमान हाल ही में निवृत्त किये गये हैं। वह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रिश्तेदार न होते, तो इस तरह के पद पर नहीं बैठ सकते थे। हसीना सरकार के सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा आर्मी चीफ सैफुद्दीन से भी अच्छे संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक, हसीना ने भारत सरकार से मदद की अपील की थी, लेकिन सरकार इस मामले में सीधे दखल देकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए विदेश मंत्रालय ने उन्हें भारत आने की सलाह दी। आंदोलनकारियों के जुलूस के पीएम हाउस की

15 वर्ष से ऊपर के कॉमर्शियल वाहनों को नहीं दें परमिट : आयुक्त

बॉक्साइट खनन एवं परिवहन को लेकर बैठक

शुद्ध वातावरण और पॉल्यूशन फ्री सिटी के लिए करें कार्य

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के कार्यालय कक्ष में आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बॉक्साइट खनन

एवं परिवहन से संबंधित बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरटीए सचिव संजीव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला राकेश कुमार गोप, जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा राजा राम प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी, गुमला विभूति कुमार, आयुक्त कार्यालय के तनवीर अहमद एवं



हिंडालको प्रतिनिधि उपस्थित थे। गुमला जिले में संचालित बैठक में लोहरदगा एवं बॉक्साइट खनन की संख्या,

व्यक्ति को खनन का लाइसेंस प्राप्त एवं बॉक्साइट खनन हेतु प्रयोग होने वाले वाहनों की संख्या पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि बॉक्साइट से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये। बॉक्साइट हेतु प्रयोग करने वाले वाहनों के सभी कागजात अद्यतन हो। उन्होंने

कहा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए कंपनियों आवश्यक कार्य करें।

समय-समय पर संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि अबतक कितने वाहनों पर परिवहन विभाग एवं खनन विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी है।

इसकी सूची देने का निर्देश दिया। वाहनों में एयर पॉल्यूशन डिवाइस को लगाया जाये। 15

वर्ष से ऊपर के वाहनों को परमिट नहीं दिया जाये। उन्होंने कहा कि माइनिंग होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई करते हुए जमीन भू-स्वामी को वापस किया जाये ताकि जगह का उपयोग करते हुए खेती संबंधित कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि शुद्ध वातावरण और पॉल्यूशन फ्री सिटी के लिए आवश्यक कार्य करें, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।



मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना से बढ़ गयी है बीजेपी की बौखलाहट : सुप्रियो

लोकप्रिय-जनप्रिय योजनाओं के बारे में भ्रम फैला रहे हैं बाबूलाल

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना का स्वागत राज्यभर की महिलाओं ने उत्साह के साथ किया है। कहा, राज्य सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस योजना को शुरू किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। ये योजना राज्य सरकार की उपलब्धियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पार्टी ने सोचा भी नहीं था कि इस योजना का स्वागत लोग इस तरह, इतनी ऊर्जा के साथ करेंगे। सुप्रियो ने कहा कि योजना के शुरुआती चरण में एक साथ कई विंडो खुल जाने के कारण सर्वर कुछ धीमा पड़ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया और तकनीकी खामियों को दूर किया गया। जेएमएम नेता ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योजना की तारीख जो कि 10 अगस्त तक थी, इसे बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक योजना का लाभ पहुंच सके। सुप्रियो ने कहा कि सरकार की इस लोकप्रिय



योजना से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गयी है। किसी भी योजना को लेकर गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करना बीजेपी की पुरानी योजना रही है। मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना को लेकर भी ये लोग कई स्थानों पर अनर्गल बातें फैला रहे हैं। सुप्रियो ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस योजना से लोग कमाई कर रहे हैं। मरांडी ने यहां तक कहा कि इस योजना के

सुप्रियो ने आगे कहा कि बीजेपी ने पहले डेमोग्राफी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके झूठ के पिटारे की सच्चाई जल्दी ही जनता के सामने आ गयी। कहा कि इन लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को छोड़ कर मजहबी उन्माद को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की। कहा कि जिस गैंग से वो खेल रहे थे, वो गैंग ही अब हवा में गायब हो चुकी है। कहा कि ऐसे माहौल में बीजेपी के पास मुद्दा नहीं होने से वो पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। कहा कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का भी विरोध किया था, जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर संवल मिला। रसेइया बहनों और आंगनबाड़ी बहनों को नियुक्तियां दी गयीं। राज्य में इसी तरह लाखों नियुक्तियां दी गयीं। ये सब बीजेपी को नहीं भा रहा है। ये सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण पर पूरी तरह से केन्द्रित है। जनता इस बात की गवाह है। मंगलवार को सुप्रियो भट्टाचार्य पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मईयां योजना आवेदन में हो रही परेशानी शीघ्र दूर होगी: कल्पना

आजाद सिपाही संवाददाता

गिरिडीह। झारखंड की महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना का 21 से 50 उम्र तक की सभी वर्गों की महिलाओं-बहनों को लाभ दिलाने के लिए प्रखंडों की पंचायतों और गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में शिविर लगाये जा रहे हैं। योजना को लेकर जिलेभर की महिलाएं-बहनें शिविर में बढ़-चढ़ कर भाग ले रही हैं।



योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वे स्वयं भी आवेदन कर रही हैं और अन्य को आवेदन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। शनिवार से ही शहरी क्षेत्र सहित पूरे जिले भर में लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने को लेकर कैंप लगाये गये थे, लेकिन कुछ कैंपों में अव्यवस्था के बीच कैंप में आवेदन जमा करने आयी महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मंगलवार को

विपक्ष के नेता अमर बाउरी को हाइकोर्ट ने किया नोटिस

रांची (आजाद सिपाही)। दलबदल मामले में जयप्रकाश भाई पटेल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइनल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किये हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त निर्धारित की है।

देश-विदेश की खबरों के लिए क्लिक करें www.azadsipahi.in

दिव्यांगों के समावेशी विकास पर फोकस कर रही सरकार: चंपाई

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि दिव्यांगजनों की सामान्य जीवन में समावेशी भागीदारी के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गयी है। वे मंगलवार को होटल बीएनआर चाणक्या में आयोजित स्टेट लेवल कंसल्टेंटिव वर्कशॉप में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।



झारखंड मूल रूप से धनी प्रदेश

उन्होंने कहा कि झारखंड मूल रूप से धनी प्रदेश है। जंगल-झाड़ से सुसज्जित है, लेकिन पिछड़ा भी है। पिछड़ेपन के लिए वह किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे इसे कैसे विकसित बनायें, इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति हो, तो हर समस्या का समाधान संभव है। सरकार उच्चतर शिक्षा के लिए लगातार सुविधाएं विकसित कर रही है। छात्रों को हर सुविधा दी जा रही है। अनाथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर भी सरकार का फोकस है। उन्होंने कार्यशाला में आये प्रमुखजनों से कहा कि उनके सुझाव लेकर वह समावेशी दिव्यांग विश्वविद्यालय की परिकल्पना को साकार करेंगे।

सरायकेला खारसावा के राजनगर प्रखंड में ओड़िशा की सीमा पर स्थित एक गांव का जिक्र करते हुए बताया कि वहां के स्कूल के नेत्रहीन हेडमास्टर कैसे शिक्षा देते थे। उनके ही कायों से प्रेरणा लेकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है।

समावेशी वातावरण बनाया होगा

कार्यशाला में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि समाज के विशेष वर्ग दिव्यांगजनों के लिए समावेशी वातावरण बनाया होगा। यह सिर्फ विभाग ही नहीं, हम सभी का दायित्व है। समावेशी दिव्यांग विश्वविद्यालय की परिकल्पना में भी यही तथ्य शामिल है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को क्षमता पहचान कर उनके विकास पर फोकस करना हमारा लक्ष्य है। दिव्यांगजनों की कुल 21 कैटेगरी हैं। उनकी कैटेगरी के अनुसार उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख उनके लिए कोर्सेज और क्लास डिजाइन करना होगा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि लातेहार जिले में बतौर उपयुक्त अपनी पदस्थापना के दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए एक नयी सुइट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसी तरह देवघर में ड्रॉग और गुरुकुल कार्यक्रम के माध्यम से 40 हजारों दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के अलावा सामान्य छात्रों के लिए भी विभिन्न योजनाएं लेकर आयेगे।

राज्य सरकार का राजकीय एंथम जीना है तो डर के जियो, जीवन में एक पल भी हंसना ना : बाबूलाल

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के लिए राजकीय एंथम लिखा है। उन्होंने टीवीट कर एंथम में लिखा है कि जीना है तो डर के जियो, जीवन में एक पल भी हंसना ना। कहा है कि प्रदेश में आये दिन हो रही चोरी से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि चोरों को संरक्षण देनेवाली हेमंत सरकार ने झारखंड में चोरी को राजकीय व्यवसाय मान लिया है, तभी तो चोरी और चोरों पर कार्यवाही करने के बजाव उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है।



तन, मन, भवन सब डोल रहा है

दूसरे टीवीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में जैसे मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों का मन झेलता रहता है, ठीक वैसे ही सरकारी भवनों की नींव भी डोल रही है। कब, कैसे, किसके ऊपर ये गिर जाये, ज्योतिषी भी नहीं बता सकते हैं। ये हेमंत सरकार का लूटखंड है। यहां सिर्फ बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, बल्कि बिल्डिंगों में घुसते समय, अपना कार्य करते समय हेलमेट की आवश्यकता और बढ़ जाती है, क्योंकि न जाने

कब कौन सी छत टूट कर आपके जीवन पर विराम लगा दे। कहीं छत से कंक्रीट और प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, तो कहीं पिलर का कोई हिस्सा, तो कहीं पूरा का पूरा भवन गिरने की तैयारी कर चुका है। यहां सुरक्षा अपने और अपने सिर की सिर्फ हेलमेट के हाथों है, सरकार का सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। हेमंत सरकार से जनता का विश्वास तो पहले ही टूट कर, गिर कर बिखर चुका है, अब भवनों और नींवों का विश्वास भी टूट कर गिरता दिखाई पड़ रहा है।

पारा शिक्षकों के साथ मीटिंग-मीटिंग खेल रही झारखंड सरकार: अमर बाउरी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने राज्य की हेमंत सरकार पर तंज कसा है। श्री बारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों के साथ केवल मीटिंग-मीटिंग खेल रही है। वहीं, दूसरी



ओर नीयत और नीति का फर्क

देखिए। असम की हिमंता सरकार ने बीते पांच वर्षों से सेवा दे रहे अनुबंधित समग्र शिक्षा असम के पारा शिक्षकों को बिना परीक्षा की औपचारिकता के नियोजित करने का फैसला लिया है। इसके लिए कुल 35,153 पदों का सृजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर

झारखंड सरकार अपने वायदे के विपरीत पारा शिक्षकों के साथ सिर्फ मीटिंग-मीटिंग खेलने का काम कर रही है। झारखंड में पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) के प्रति राज्य की सरकार संवेदनहीन है। सरकार का मकसद इन्हें टग कर फिर से इनका वोट लेना है।

गडकरी करेंगे झारखंड सहित चार राज्यों की 100 करोड़ से अधिक की हाइवे प्रोजेक्ट की समीक्षा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। केंद्रीय सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड सहित चार राज्यों के हाइवे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। 12 और 13 अगस्त को इस संबंध में केंद्रीय सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैठक नयी दिल्ली में आहूत की है, जिसमें इन राज्यों के एनएचपीआइ के अधिकारी और चीफ इंजीनियर शामिल

होंगे। 100 करोड़ लागत से अधिक की हाइवे परियोजनाओं की समीक्षा की जायेगी। झारखंड, ओड़िशा, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश की चालू योजनाओं सहित लंबित योजनाओं का केंद्रीय मंत्री हाल लेंगे। सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याओं का भी निदान कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जायेगा। केंद्र में रिज्यू को

देखते हुए झारखंड से भी तैयारी चली रही है। कोलकोता-रांची-वाराणसी कॉरिडोर निर्माण में आ रही जमीन संबंधी बाधाओं पर भी चर्चा की जायेगी। इसके अलावा रांची-कुड़ु-वाराणसी फोरलेन रोड, रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनएच 33 के बैलेस वर्क सहित अन्य बड़ी सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की जायेगी।



झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर भाजपा का पलटवार असफल सरकार की असफल योजनाओं की है एक लंबी दास्तां : प्रतुल शाहदेव

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के रिकॉर्ड पर ही प्रश्न चिह्न खड़ा किया। प्रतुल ने कहा कि जो सरकार आज तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन पायी, 1932 का खतियान लागू नहीं कर पायी, बेरोजगारों को 5000 एवं 7000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पायी, ऐसी सरकार से उसकी राजनीतिक मृत्यु शैया पर किसी नयी योजना के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद करना भी बेमानी है। प्रतुल ने कहा कि दरअसल इस सरकार के भ्रष्टाचार ने झारखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल घूम आये। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री अभी जेल में हैं। मुख्यमंत्री के तमाम दरबारी जेल

■ महिला सम्मान योजना के जरिए सरकार आपने लूट, खसोट और असफलताओं से ध्यान हटाने की असफल कोशिश कर रही

■ वादा था महिलाओं को चूल्हा खर्वों में 2000 प्रतिमाह और गरीब परिवारों को 6000 प्रतिमाह देने का और मात्र 1000 रुपये प्रति

माह देने का फॉर्म भराया जा रहा ■ महिला उतपीड़न की घटनाओं की संख्या चरम पर, सरकार इस मुद्दे पर मौन क्यों?

के भीतर हैं। राज्य में हाहाकार मचा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गयी है। इन सबसे ध्यान बांटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना तैयारी के 'मईयां सम्मान योजना' ले आये। प्रतुल ने कहा कि पहले ही चार दिनों में इस योजना के प्रति सरकार की मंशा को कलई खुल गयी। अधिकांश जगह सर्वर डाउन है। बिचौलिये हावी हैं। फार्म जमा नहीं हो पा रहा है। यह स्पष्ट दिखा रहा है कि चुनाव के देख कर सरकार की ओर से की गयी हड़बड़ी ने बड़ी गड़बड़ियां करा दीं। प्रतुल ने कहा कि इस सरकार में महिला उतपीड़न की घटनाओं ने झारखंड के पहले 19 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पांच वर्षों में लगभग 7000 बहू-बेटियों की



इज्जत लूटी गयी। सरकार ने आज तक श्वेत पत्र जारी करके यह नहीं बताया कि इसमें से कितने अभियुक्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलायी गयी। जानकारी के मुताबिक बहुसंख्य मामलों में तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। प्रतुल ने कहा कि यह सरकार लूट, खसोट में इतनी लीन रही कि उसने अपने निश्चय पत्र को भी पलट कर नहीं देखा। एक बार

निश्चय पत्र को देखने से पता चल जाता है कि उसमें की गयी कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई। अब झामुमो को यह भी याद नहीं कि उसके मेनिफेस्टो में महिलाओं को चूल्हा भत्ता में 2000 प्रतिमाह देने का प्रावधान है प्रतुल ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब अपने निश्चय पत्र में किये गये वायदे भी याद नहीं हैं। आज की प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके मेनिफेस्टो में चूल्हा भत्ता का कोई जिक्र नहीं है, जबकि उनके 'निश्चय पत्र' के 'महिलाओं के अधिकार' चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि महिलाओं को प्रतिमाह 2000 चूल्हा खर्व के रूप में मिलेगा।

हर मोर्चे पर विफल हो चुकी राज्य सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी : नरेंद्र पांडेय

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने किया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा, मोदी सरकार की गिनायी उपलब्धियां

आजाद सिपाही संवाददाता
मेदिनीनगर। आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर वरिय भाजपा नेता सह पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। श्री पांडेय ने विश्रामपुर विस क्षेत्र के राजहरा, कविलासी, लेदुका, बंदला, बसना, ब्रह्मोरीया, अमावा, सेमरी, गुरहा, मुरमा, केतात, डंडोला, गोरामा, बरवाडीह सहित कई गांवों में जाकर लोगों से मिले। इस दौरान कई गांवों में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान हेतु सार्थक पहल करने का भरोसा दिलाया। श्री पांडेय ने



उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना एवं सावित्री बाई फुले योजना की तर्ज पर ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था करनी चाहिए। आंगनवाड़ी सेविका, पंचायत सचिव या मुखिया के द्वारा आवेदन लेने की प्रक्रिया को अपनाया चाहिए, ताकि महिलाओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्री सिंह ने सरकार की ऑनलाइन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हर काम

अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसी निक्कमी सरकार को जानता आगामी विस चुनाव में

उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने ग्रामीणों से भाजपा को अपना समर्थन देते रहने का अपील भी किया। मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सिंह सहित भाजपा के कई नेता कार्यक्रता मौजूद थे।

महिलाओं के लिए संकट बनी 'मंडियां सम्मान योजना' : कमलेश कुमार सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गयी 'मंडियां सम्मान योजना' अब 'महिला परेशान योजना' बन गयी है। हुसैनाबाद हरिहरगंज के विधायक और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने इस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार का हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला महिलाओं के लिए मुसीबत बन गया है। श्री सिंह ने कहा कि प्रतिदिन बढ़ी संख्या में महिलाएं अपना घर-बार छोड़कर पंचायत सचिवालयों का चक्कर लगा रही हैं, फिर भी उनका आवेदन अपलोड नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अगर मुख्यमंत्री इस योजना को इमानदारी के साथ लागू करना चाहते हैं तो



ऑनलाइन करना चाहती है, लेकिन इसके मुताबिक व्यवस्था नहीं करती। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता रथ चलाने और बड़े बड़े विज्ञापन देने की जगह बेहतर पोर्टल का निर्माण करना चाहिए। मंडियां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए गांव और शहर की महिलाएं आवेदन के साथ शिविरों में दिन गुजार रही हैं और घर जाने के बाद निराश अपने धर वापस लौट रही हैं।

आजाद सिपाही संवाददाता
मेदिनीनगर। पलामू एस्प्री की गुप्त सूचना के आलोक में सतबरवा एनएच से सटे दुलसुलमा स्थित महेंद्र लाइन होटल के समीप भरत भूषण के गोडाउन में अवैध केमिकल के हो रहे व्यापार की जानकारी मिलते ही सतबरवा पुलिस ने छापेमारी की। जैसे ही पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो अपना नाम मुकुल मंडल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर थाना क्षेत्र के तानसेन रोड दुर्गापुर बताया। उसने अपने स्वोकार किया कि रेहला कास्टिक सोडा प्लांट से निकलने वाली गाड़ियों के झड़वर

कास्टिक सोडा लाई की अवैध खरीद बिक्री करने वाले सप्लायर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

से हमारा सेटिंग रहता है। जो भी गाड़ी रांची, टाटा, बोकारो जाती है उनसे माल खरीद कर उसे बंगाल में बेंच देते हैं। और जितना माल निकालते हैं उतना उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। सतबरवा थाना प्रभारी बताया कि इस तरह के मामले बोकारो और दुर्गापुर में इसके द्वारा किया जाता रहा है और वह जेल भी गया है। मालूम हो कि कास्टिक सोडा लाई ग्रासिम



इंडस्ट्रीज के केमिकल्स डिवीजन रेहला से कई अन्यत्र जगहों पर टैंकर में लोड कर भेजा जाता है जो काफी कोस्टली होता और बाजार में साबुन बनाने वाली कंपनियों में अच्छे दामों में बिकता है। सतबरवा पुलिस ने गोडाउन से 15 ड्रम में कास्टिक सोडा भरा हुआ बरामद किया है। और करीब दो सेन्टैक्स की बड़ी बड़ी टंकी और ड्रम, इलेक्ट्रिक मोटर बरामद किया है।

आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जपला में कक्षा-सप्तम से दशम तक के छात्राओं को महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी द्वारा मोटिवेशन क्लास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी, विद्यालय प्रबंधक रणवीर सिंह के उपाध्यक्ष डॉ सत्येंद्र चंदेल, प्रधानाचार्य कुश पाण्डेय संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन किया और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा आए हुए अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि शिशु मंदिर के बच्चों में बाल्य काल से संस्कार भरा जाता है, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि छात्राओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचना चाहिए और बहनों को गुड टच और बेड टच के बारे में बताया गयो डॉ सत्येंद्र चंदेल जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजकुमार सिंह, हर्षद उपाध्याय, छाया कुमारी एवं अन्य शिक्षक-शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं को मिली मोटिवेशनल शिक्षा



आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। प्रखंड अंतर्गत सुदुर्ग्वर्ती क्षेत्र के राजकीय कृत मध्य विद्यालय पथरा में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामराज पासवान तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलनाथ वर्मा के उपस्थिति में छात्र-छात्राओं के बीच विभाग से प्राप्त क्रिकेट का वितरण किया गया। क्रिकेट मिलने पर बच्चों के चेहरों पर काफी खुशी नजर

आया मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पठन-पाठन की सामग्री मिलने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ती है। मौके पर सहायक शिक्षक विनय कुमार रवि, सहायक अध्यापक कविंद्र कुमार पासवान, धीरेंद्र कुमार चौधरी तथा सहायक अध्यापिका शमीम बेगम समेत काफी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

ग्रामीणों ने पुल कार्य निर्माण स्थल के पास डायवर्सन की मांग की



आजाद सिपाही संवाददाता
हरिहरगंज/ पलामू। प्रखंड क्षेत्र के कुलहिया पंचायत अंतर्गत ग्राम लादी वादी बतरे नदी पर पुल कार्य निर्माण के दौरान डायवर्सन नहीं दिए जाने पर संवेदक के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने काफी स्थल पर पहुंच कर आक्रोश जताते हुए नदी पर डायवर्सन की मांग किया है। ग्रामीणों ने कहा की पुल निर्माण कार्य से पहले

हम लोगों ने चंदा तसिल कर डायवर्सन बनाया था। संवेदक द्वारा मनमानी करते हुए डायवर्सन को तोड़ दिया गया और दूसरा डायवर्सन नहीं बनाया गया। जिससे आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। आक्रोश जताने वालों में छात्र राजद प्रखण्ड अध्यक्ष दीपक कुमार यादव, पूर्व मुखिया मथुरा रजक, वीरेंद्र यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हैं।

करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत

आजाद सिपाही संवाददाता
पांकी/ पलामू। पांकी थाना क्षेत्र के हुरलौंग में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हो गयी। दोनों धनरोपनी के लिए खेत तैयार कर रहे थे। खेत में बिजली की तार पहले से गिरा हुआ था, इस बात की जानकारी नागेंद्र चंद्रवंशी और पुत्र पिंटू चन्द्रवंशी को नहीं थी। नागेंद्र चन्द्रवंशी खेत में जैसे ही दाखिल हुए वह बिजली के चपेट में आ गये। पिता को बचाने के लिए उनके बेटे पिंटू चन्द्रवंशी खेत में दाखिल हुए और वे भी करंट की चपेट में आ गये। बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली का कनेक्शन काटा और दोनों को इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज एंड



हॉस्पिटल ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मियों के लापरवाही के कारण घटना घटी है। पिता पुत्र की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इधर

घटना की सूचना पाकर क्षेत्रीय विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांडस बंधाया एवं मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया।

चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार



हरिहरगंज/ पलामू (आजाद सिपाही)। शहर के अररुआ मोड स्थित वाहन चेकिंग के दौरान हरिहरगंज पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी करने के आरोप में थाना कांड संख्या 111/24 दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में पुन सह थाना प्रभारी प्रभारी चंदन कुमार ने बताया की भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5), 3(5) के अंतर्गत थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी गोविंद मेहता के 21 वर्षीय पुत्र विकास कुमार और सरसोत निवासी बुटाई मिस्त्री के 29 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

मध्य विद्यालय पथरा के छात्र-छात्राओं के बीच क्रिकेट का वितरण



आजाद सिपाही संवाददाता
हुसैनाबाद। प्रखंड अंतर्गत सुदुर्ग्वर्ती क्षेत्र के राजकीय कृत मध्य विद्यालय पथरा में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामराज पासवान तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलनाथ वर्मा के उपस्थिति में छात्र-छात्राओं के बीच विभाग से प्राप्त क्रिकेट का वितरण किया गया। क्रिकेट मिलने पर बच्चों के चेहरों पर काफी खुशी नजर

आया मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पठन-पाठन की सामग्री मिलने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ती है। मौके पर सहायक शिक्षक विनय कुमार रवि, सहायक अध्यापक कविंद्र कुमार पासवान, धीरेंद्र कुमार चौधरी तथा सहायक अध्यापिका शमीम बेगम समेत काफी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

स्पोर्ट्स

भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए किया क्वालिफाई

एजेंसी
पेरिस। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलिंपिक 2024 में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मंगलवार को खेले गए पुरुषों के भाला फेंक क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का शानदार शो फेंका, जो 84 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन से काफी अधिक था। भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में



का शो किया। पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में जगह बनाने के लिए एथलीटों को क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 84 मीटर की दूरी को पार करना था, जिसे नीरज ने आसानी से पार कर लिया। नीरज अब फाइनल में अपना खिताब बरकरार रखने के इरादे से उतरेगे। अगर वह खिताब जीतते हैं तो ओलिंपिक व्यक्तिगत वर्ग में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनेंगे। विश्व चैंपियन नीरज ने 87.58 मीटर के प्रयास के साथ टोक्यो ओलिंपिक का स्वर्ण पदक जीता था।

यूक्रेन की उकसाना लिवाच को हरा सेमीफाइनल में पहुंचीं विनेश फोगाट

एजेंसी
पेरिस। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलिंपिक 2024 में महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की उकसाना लिवाच को 7-5 से हराया। सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 10:25 बजे खेला जायेगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विनेश ने पहले पीरियड में 2-0 की बढ़त ले ली। दूसरे पीरियड में लिवाच ने वापसी की लेकिन



विनेश ने उनकी चुनौती को रोक दिया। यूक्रेनी की पहलवान को पछड़ कर विनेश ने 7-5 से जीत दर्ज कर ली। इससे पहले राउंड ऑफ 16 में भारतीय स्टार ने 2020 टोक्यो ओलिंपिक की चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी थी।

भाजपा नेता ने कार्यपालक पदाधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत



आजाद सिपाही संवाददाता
हरिहरगंज/ पलामू। कार्यपालक पदाधिकारी फैजुर रहमान अंसारी को भाजपा नेता सतगावा निवासी रविंद्र पासवान ने शिष्टाचार मुलाकात के दौरान गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हरिहरगंज शहरी क्षेत्र की कई समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र ने बताया कि उन्हें शहरी क्षेत्र अंतर्गत जर्जर और बजबजाती नालियों की सफाई कराने, जर्जर पथों की मरम्मत कराने सहित पीएम आवास योजना के लाभुकों को सही समय पर किशतों के रूप

समस्याओं का निदान के लिए आवेदन देने की बात कही। मौके पर सीटी मैनेजर नजीबुल्लाह अंसारी, सामुदायिक संगठन कर्ता विचित्रा कुमारी, मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी आदि मौजूद थे।

